**समक्ष - के कन्नन जे.**

कमल सिंह और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

CWP No. 14005 OF 2008

30 जून 2010

**भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-एक नए जिले का निर्माण-कुछ कर्मचारियों को उनकी सहमति के बिना प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित करना-प्रतिनियुक्तिकर्ताओं के दावों को नजरअंदाज करते हुए कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति देना-प्रतिनियुक्ति पर याचिकाकर्ताओं को बिना सहमति के नवगठित जिले में स्थानांतरित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई बचाव योग्य नहीं है- याचिकाओं को लागत के साथ अनुमति दी गई, प्रतिनियुक्ति के आदेश रद्द कर दिए गए और याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित पदों पर वापस भेजे जाने का हकदार माना गया।**

अभिनिर्णित - याचिकाकर्ताओं को सहमति के बिना नवगठित जिले में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई अक्षम्य है। सभी व्यक्ति अपने मूल पदों पर वापस भेजे जाने के हकदार हैं। उनकी वरिष्ठता की गणना जिला गुड़गांव में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से की जाएगी और उस तारीख के बाद उस पद पर रहने वाले व्यक्तियों

को जो भी पदोन्नति की पेशकश की गई थी, वह संबंधित याचिकाकर्ताओं को उस तारीख को दी जाएगी जब बाद में नियुक्ति की पेशकश की गई थी। पदोन्नति। इसका कोई मतलब नहीं होगा कि जो पद याचिकाकर्ताओं ने खाली किया है उसे बाद में नई नियुक्तियों से भरा गया है। यदि उन्हें अधिशेष माना जाता है, तो उन्हें या तो नवनिर्मित जिले में पुनः समायोजित किया जा सकता है या उनके भेजे गए लोगों को कानून के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा। यदि डीआरडीए गुड़गांव में बाद में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की कार्यवाही के उदाहरण पर किसी भी अदालत के किसी भी आदेश के आधार पर ऐसे अधिशेष पदों की सेवा समाप्त करना असंभव हो जाता है, तब भी इसे याचिकाकर्ताओं को इनकार करने के आधार के रूप में नहीं लिया जाएगा। प्रत्यावर्तन का अधिकार. याचिकाकर्ताओं का प्रत्यावर्तन प्राप्त करने का अधिकार उस न्यायालय को दिखाया जाएगा जिसमें याचिका लंबित है और यह प्रतिवादियों के लिए न्यायालय के निर्देशों के अधीन उचित निर्णय लेने के लिए खुला होगा, जिसके लिए वे कानून के अनुसार हकदार होंगे।

(Para 8)

याचिकाकर्ताओं की ओर से सुश्री प्रीति खन्ना, वकील।

उत्तरदाताओं संख्या I और 2 के लिए रवि दत्त शर्मा, डीएजी हरियाणा।

प्रतिवादी संख्या 3 और 5 के लिए वकील दिनेश शन्ना।

प्रतिवादी संख्या 4 और 6 के लिए वकील विकास बिश्नोई

**के. कन्नन, जे.**

(1) सभी याचिकाकर्ता जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डीआरडीए) मेवात के कार्यालय में प्रतिनियुक्त हैं, जिन्होंने पहले डीआरडीए, गुड़गांव के कार्यालय में स्थायी रोजगार किया था। गुड़गांव से मेवात में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण उस समय हुआ जब हरियाणा राज्य में एक नया जिला बनाया गया था, जो पहले गुड़गांव जिले का एक हिस्सा था। अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 7 जून, 2005 को जारी किए गए कार्यालय आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के अस्थायी स्थानांतरण नव निर्मित मेवात जिले में कार्यालय के उचित कामकाज के लिए किए गए थे। स्थानांतरण आदेशों में विशेष रूप से कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों को डीआरडीए, मेवात में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, लेकिन वे किसी भी प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार नहीं होंगे। इसके बाद वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया कि अगले आदेश तक डीआरडीए मेवात में कार्यरत रहेंगे।

(2) याचिकाकर्ताओं की शिकायत प्रतिनियुक्ति पर मौजूद व्यक्तियों में से थी जब 28 मार्च, 2006 को कुछ व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के आदेश दिए गए थे, जब 8वें याचिकाकर्ता को बलबीर सिंह के स्थान पर डीआरडीए मेवात में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था, जो वह डीआरडीए, फ़रीदाबाद में एक लेखाकार थे, जिन्हें शुरू में इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 4 अक्टूबर, 2007 को एक अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति

रद्द कर दी गई और उसे गुड़गांव स्थित उसके मूल प्राधिकारी में वापस भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं का प्रयास यह दिखाने का था कि प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण बिना किसी तर्क के किए गए थे और उत्तरदाता केवल पिक एंड चूज़ दृष्टिकोण अपना रहे थे। उनकी शिकायत को तब और आयाम मिल गया जब गुड़गांव में कुछ अधिकारियों को स्थायी कर दिया गया और पदोन्नति दी गई, लेकिन याचिकाकर्ताओं, जो स्थायी अधिकारी थे और पदोन्नत कर्मचारियों से वरिष्ठ थे, पर विचार तक नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं की प्रतिनियुक्ति द्वारा रिक्त किए गए पदों को समय-समय पर सीधी नियुक्तियों द्वारा भरा जा रहा था, बिना किसी याचिकाकर्ता को प्रत्यावर्तन का विकल्प दिए। यह वह समय था जब याचिकाकर्ताओं ने 14 सितंबर, 2007 को अपने आवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी ताकि अस्थायी कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, जो याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ थे। 31 जनवरी, 2008 को प्राप्त जानकारी (अनुलग्नक पी-6) से निम्नलिखित पता चला:-

> “1. यह कहा गया था कि डीआरडीए, मेवात में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों की वरिष्ठता को डीआरडीए, गुड़गांव में पदोन्नति/नियुक्ति करते समय ध्यान में नहीं रखा गया था।
>
> 2. ऐसी पदोन्नतियाँ करते समय, प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए डीआरडीए, मेवात के कर्मचारियों की सहमति उन पदों पर वापस लाने और पदोन्नत करने के लिए नहीं ली

गई थी जो याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्तियों को दी गई थीं। हालाँकि, अतिरिक्त उपायुक्त, गुड़गांव के कार्यालय द्वारा 4 दिसंबर, 2006 को जारी एक ज्ञापन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सभी राज्य विभागों/डीआरडीए से प्रतिनियुक्ति के संबंध में पूछा गया था और प्रतियां डीआरडीए मेवात को चिह्नित की गई थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था।

3. किसी के तहत पदोन्नति/नियुक्ति डीआरडीए कर्मचारी सेवा नियमावली, 2001 के विशिष्ट नियम तहत नहीं की गई थी ।

4. डीआरडीए, मेवात में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों के दावों को नजरअंदाज करने के लिए निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग, चंडीगढ़ से कोई सहमति नहीं ली गई थी।

यह जानकारी हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक की तरह ही सामने आई, जब उन्होंने 7 मार्च, 2008 को आदेश दिया था कि कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/स्थानांतरण डीआरडीए के उपायुक्तों द्वारा अपने स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। जबकि वे सेवा नियमों के अनुसार ऐसा आदेश देने में सक्षम नहीं थे। उस आदेश में यह प्रस्तुत किया गया था कि विभाग को उपायुक्तों के ऐसे कार्यों के मद्देनजर कई कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा था और इसकी जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों पर डाल दी गई थी जो सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना आदेश जारी कर रहे थे। यानी याचिकाकर्ताओं ने

एकजुट होकर प्रतिनियुक्ति के आदेशों को रद्द करने और उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेजने के लिए वित्तीय आयुक्त को एक अभ्यावेदन दिया। याचिकाकर्ताओं ने 4 जून, 2008 को अपने पत्र के माध्यम से यह भी चेतावनी दी कि यदि संचार से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वे न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। इसी तरह का पत्र गुड़गांव के अतिरिक्त उपायुक्त को भी भेजा गया था।

(3) यह पाते हुए कि नोटिस से उनकी वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि कानून में खराब होने और एक परमादेश जारी करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त किए बिना उन्हें गुड़गांव से मेवात में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश जारी किए गए। याचिकाकर्ताओं को तुरंत उनके मूल विभाग में वापस भेजने और वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति के लिए उनके संबंधित दावों पर विचार करने के लिए आधिकारिक उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 को निर्देश दिया गया। उत्तरदाता संख्या 1 से 3, जो वित्तीय आयुक्त, विशेष सचिव और गुड़गांव के उपायुक्त हैं, ने लिखित बयान दाखिल किए हैं। एक ओर उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त, गुड़गांव और दूसरी ओर उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त, मेवात अपने-अपने अलग-अलग बयान देकर भाग गए हैं, उत्तरदाताओं का तर्क है कि किसी धारणा की कोई गुंजाइश नहीं है याचिकाकर्ताओं के लिए कि वे स्थायी कर्मचारी थे और यह नीति का मामला था कि डीआरडीए के पास कोई स्थायी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। जब याचिकाकर्ताओं को मेवात में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो गुड़गांव के बड़े जिले का एक हिस्सा था, तो

उनकी सेवाओं को मेवात के क्षेत्र में ही समाहित कर लिया गया था, जो वैकल्पिक स्थिति सामने आई थी वह यह थी कि प्रतिष्ठान की सेवाओं को समाप्त कर सकता था। जब एक नया जिला बनाया गया तो अधिकारी। आगे यह तर्क दिया गया है कि जिला विकास ग्रामीण एजेंसी सेवा नियम, 2001 द्वारा प्रदान की गई सीमा को छोड़कर सेवा नियमों को सरकार के बराबर नहीं माना गया है। एजेंसी का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण के कार्य को संबोधित करना था विकास और कर्मचारियों के हितों को इस "ग्रामीण समस्याओं के निवारण के प्राथमिक उद्देश्य" के अधीन रखना। हालाँकि सभी याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरित कर नवगठित जिले मेवात में प्रतिनियुक्ति पर तैनात बताया गया था। वे वास्तव में उसी भौगोलिक क्षेत्र में सेवा कर रहे थे जैसे वे गुड़गांव के पहले बड़े जिले में काम कर रहे थे। इसलिए, उत्तरदाताओं ने यह तर्क देने की कोशिश की कि अभिव्यक्ति "प्रतिनियुक्ति" का उपयोग स्वयं तकनीकी अर्थ में नहीं किया गया था, बल्कि इसे आम बोलचाल की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए कि उन्हें उसी स्थान पर काम करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी। एक अलग जिला, जिसे हाल ही में गुड़गांव से अलग किया गया था। नियमों में कानूनी अर्थ में किसी भी प्रतिनियुक्ति का प्रावधान नहीं था और सभी याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं द्वारा स्थानांतरण पर भेजा गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था, जिसे उत्तरदाता स्थानांतरित लोगों की तथाकथित धारणा को इसका श्रेय देंगे कि उन्हें नव निर्मित जिले में तेजी से पदोन्नति मिलेगी। याचिकाकर्ताओं को किसी भी दूर-दराज के इलाके में स्थानांतरित

नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें गुड़गांव से अलग होकर हरियाणा में बने पूर्ववर्ती जिले में उसी स्थान पर बरकरार रखा गया है। नये जिले के गठन के द्वारा उन्हें नये जिले में आवंटित किये जाने पर भी उसी स्थान पर समायोजित किया जाना था। केवल जिले का नाम बदला गया है अन्यथा याचिकाकर्ताओं को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। यानी स्थान परिवर्तन और याचिकाकर्ताओं का स्थानांतरण एक नए जिले के निर्माण के अनुसार आवश्यकता और आवश्यकता का परिणाम था। नए जिले में प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए मौजूदा जिले से कार्यबल को उठाया जाना था और यदि नया जिला नहीं बनाया गया होता, तो यह पूरी तरह से संभव होता कि याचिकाकर्ताओं को मेवात में तैनात किया जाता। यह क्षेत्र पूर्ववर्ती गुड़गांव जिले का हिस्सा है। जिन स्थानों पर याचिकाकर्ताओं को तैनात किया गया था वे नूंह, फिरोजपुर झिरखा थे। ताओरू और पुन्हाना, जो पहले गुड़गांव जिले का हिस्सा थे।

(4) रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 को याचिकाकर्ताओं की शिकायतों में समान औचित्य दिखाई देता है कि उनमें से कुछ, जिन्हें मेवात जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था, को पदोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया गया था, जो यदि वे गुड़गांव जिले में बने रहते तो उन्हें प्राप्त होता। निदेशक, ग्रामीण विकास, हरियाणा श्री. विमल चंद्रा ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण करने के लिए, डीआरडीए, गुड़गांव को याचिकाकर्ताओं की डीआरडीए, मेवात में प्रतिनियुक्ति के आदेशों पर पुनर्विचार/संशोधन करना था और डीआरडीए में पदोन्नति/नियुक्ति

के नए आदेश दिए जाने चाहिए। , गुड़गांव उसके बाद रिक्तियों के खिलाफ। विशेष रूप से उन लोगों के हितों का जिक्र करते हुए, जिन्हें गुड़गांव में याचिकाकर्ताओं के लिए बाद में नियुक्त किया गया था और जिन्होंने पदोन्नति प्राप्त की थी, हलफनामे में कहा गया है कि पुन: समायोजन में लगभग चार से पांच महीने लगेंगे और उन्होंने की गई नियुक्तियों पर पुनर्विचार पूरा करने की मांग की थी। छह महीने की अवधि में, यह शपथ पत्र और गुड़गांव के अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा भेजा गया संचार स्पष्ट रूप से 7 मार्च को जारी विशेष सचिव और निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग के संचार से निकलने वाली प्रशासनिक चेतावनी को शांत करता प्रतीत होता है। 2008. जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।

(5) संसदों की दलीलों से पता चलता है कि जब याचिकाकर्ताओं को मेवात जिले में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, तो उत्तरदाता प्रतिनियुक्ति की शर्तों को तबादलों का पर्याय मान रहे थे और ऐसे तबादलों को सभी याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया था। नए जिले के गठन के कारण स्थानांतरण भी आवश्यक हो गए थे और याचिकाकर्ताओं को गुड़गांव जिले के आकार में कमी के कारण पदों की संख्या में गिरावट के लिए अपनी नौकरियों की सूची नहीं होने का लाभ मिला। याचिकाकर्ता खुद को गुड़गांव में स्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं मान सकते थे और उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता मेवात जिले में काम करने के बजाय गुड़गांव जैसे शहर में वापस आने की इच्छा से प्रेरित थे। यहां तक कि दलीलों के माध्यम से कवर किए गए मामले के अलावा कुछ अतिरिक्त तथ्य दस्तावेजों के माध्यम से

लाए गए हैं जो दलीलों द्वारा शासित नहीं हैं। मेवात के उपायुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने बहस के समय बिना किसी आवेदन के दूसरे याचिकाकर्ता किशन लाल को क्लर्क-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटर के उनके मूल पद से जारी किए गए पदोन्नति आदेश से संबंधित कुछ कार्यालय आदेश अदालत के समक्ष पेश किए। 28 मार्च, 2007 के आदेश द्वारा उच्च वेतनमान के साथ जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर। श्री सोराज शर्मा (चौथे याचिकाकर्ता) को श्योराज सिंह कहा जाता है, जो मेवात में चपरासी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें 25 जुलाई, 2007 को क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह आदेश हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इसे बाद में 14 दिसंबर, 2007 को वापस ले लिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका के बाद, जब याचिकाकर्ताओं के मेवात में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा बनाई गई रिक्तियों में गुड़गांव में नव नियुक्त व्यक्तियों को वापस लेने की मांग की गई थी, तो उन्होंने रिट याचिकाएँ दायर कीं और स्थगन आदेश प्राप्त किए। कर्मचारी थे: (i) विशाल गर्ग; (ii) अजय स्वरूप; (iii) सुरेंद्र सिंह; (iv) ज़िल्क सिंह; (v) संजय सिंह; (vi) धर्मवीर; (vi) बलजीत सिंह।

(6) उत्तरदाताओं के कार्य कम से कम कहने योग्य हैं और विशेष रूप से गुड़गांव और मेवात के उपायुक्तों के कार्य सबसे अधिक मनमाने हैं। यह तर्क देना मूर्खतापूर्ण है कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि प्रतिनियुक्ति क्या होती है और उन्हें केवल स्थानांतरण के आदेशों का पर्याय माना जाता था। जबकि स्थानांतरण सिविल सेवा की संवैधानिक योजना और संबंधित नियमों में सेवा का मात्र एक बंधन हो सकता है। ऐसे नियमों के अभाव में स्थानांतरणों को केवल

औचित्य प्राप्त नहीं हो सकता। यदि ऐसे स्थानांतरण किए जाते हैं और उनमें रोजगार की कोई शर्त उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो वे स्थानांतरित कर्मचारियों से सहमति प्राप्त करना जारी नहीं रख सकते हैं। नतीजतन, यदि याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उन्हें उनकी सहमति के बिना गुड़गांव जिले से नवगठित जिले मेवात में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो यह तर्क देना कोई बचाव नहीं हो सकता है कि यदि कोई नया जिला नहीं बनाया गया होता तो उन्हें उसी के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता था। एक ही जिला. यदि नियुक्ति की शर्तों में इसका प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसा औचित्य भी गलत है। यदि यह अत्यावश्यक था तो वे थे नवगठित जिले में स्थानांतरित होने के लिए आवश्यक होने पर, उन्हें या तो नवगठित जिले में स्थानांतरित होने का अवसर दिया जाना चाहिए या समाप्ति नोटिस के साथ सेवा दी जानी चाहिए और फिर से कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से सेवाएं समाप्त करनी चाहिए। केवल अत्यावश्यक होने के कारण व्यक्तियों को दूसरे जिले में स्थानांतरित करना अस्वीकार्य है।

(7) यहां तक कि यह तर्क भी कि इन सभी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए, कोई भी नई नियुक्ति संभव थी और याचिकाकर्ताओं के मेवात जिले में स्थानांतरण द्वारा बनाई गई रिक्तियों में पदोन्नति की कोई भी पेशकश भी संभव थी। समान रूप से अस्थिर. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने मौलिक स्थिति पर कई निर्णयों पर बड़े पैमाने पर भरोसा किया है कि प्रतिनियुक्ति बिना सहमति के नहीं की जा सकती है

और प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को मूल विभाग में ग्रहणाधिकार का अधिकार है और पदोन्नति के आदेश उनकी संबंधित वरिष्ठता के संदर्भ के बिना नहीं किए जा सकते हैं। अभिभावक सेवा. मैं उनका हवाला केवल उस कानूनी स्वाद को स्वीकार करने के लिए दे रहा हूं जो याचिकाकर्ता मांग को न्याय देने के लिए देना चाहते हैं। **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाम डॉ. के.एस. जावतकर और अन्य**[1] के मामले में, यह माना गया कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विशेष केंद्र में कर्मचारी की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को सेवा के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप शिक्षक की सेवा दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरित नहीं हो सकती है और मूल रूप से नियुक्त शिक्षक जारी रहेगा। प्रथम नियुक्त प्राधिकारी का कर्मचारी होना। यदि कभी पद समाप्त करने हों तो अंतिम आओ पहले जाओ का सिद्धांत लागू होना चाहिए। कानून की स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि किसी भी कर्मचारी को एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता के पास भेजे बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। **उड़ीसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सर्विस एसोसिएशन बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य**[2] मामले में, कानून की स्थिति की पुष्टि की गई थी कि प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित रोजगार से प्रत्यावर्तन को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि मूल कैडर में केवल सीमित पद उपलब्ध थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिनियुक्तिकर्ता मूल कैडर में अपने ग्रहणाधिकार के अनुसार प्रत्यावर्तन के हकदार हो सकते हैं। **पंजाब राज्य और अन्य बनाम इंदर सिंह और अन्य**[3] में, प्रतिनियुक्ति की अवधारणा

[1] 1989 Supp. (1) SCC 679
[2] (1998) 2 SCC 563
[3] AIR 1998 SC 7

को यह कहकर समझाया गया था कि इसका मतलब कैडर के बाहर या मूल विभाग के बाहर सेवा है। प्रतिनियुक्ति में "किसी कर्मचारी को उसके कैडर के बाहर किसी अन्य विभाग में अस्थायी आधार पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरित करना शामिल था। प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के बाद, कर्मचारी को उसी पद पर कब्जा करने के लिए मूल विभाग में वापस आने का अधिकार था जब तक कि इस बीच में। उन्होंने भर्ती नियमों के अनुसार अपने मूल विभाग में पदोन्नति अर्जित की थी। मुद्दा यह था कि स्थानांतरण तैनाती के सामान्य क्षेत्र से बाहर है या नहीं, इसका निर्णय उस सेवा या पद को नियंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जहां से कर्मचारी स्थानांतरित हुआ होगा। **सत्य नारायण पारीक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**[4] मामले में, जिस व्यक्ति को अस्थायी रूप से कनिष्ठ पद पर स्थानांतरित किया गया था, उसका मूल विभाग में ग्रहणाधिकार था, उसे निलंबित नहीं किया जा सकता था। **उमापति चौधरी बनाम बिहार राज्य और अन्य**[5] में, प्रतिनियुक्ति को मूल विभाग के रूप में एक विभाग या कैडर के एक कर्मचारी (आमतौर पर प्रतिनियुक्ति के रूप में जाना जाता है) के रूप में अलग करने के लिए किया गया था। या उधार देने वाला प्राधिकारी) किसी अन्य विभाग या कैडर या संगठन को (आमतौर पर उधार लेने वाला प्राधिकारी कहा जाता है)। सार्वजनिक सेवा में अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता जनहित में उत्पन्न होती है।

---

[4] AIR 1997 SC 256
[5] AIR 1999 SC 1948

प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सहमतिपूर्ण है और इसमें अपने कर्मचारी की सेवाओं को उधार देने के लिए नियोक्ता का स्वैच्छिक निर्णय और उधार लेने वाले नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवाओं की स्वीकृति शामिल है। इसमें प्रतिनियुक्ति पर जाने या न जाने के लिए कर्मचारी की सहमति भी शामिल है। **मैसूर राज्य बनाम एम.एच. बेल्लारी**[6], प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने माना कि किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी की सेवा को नियम द्वारा मूल विभाग में सेवाओं के बराबर माना जाता है और यह सेवाओं के बीच का समीकरण है। दो विभागों में से जो सिविल सेवा नियमों के नियम 50(बी) का आधार बनते हैं। इसका कारण यह है कि जिस पद पर वह वास्तव में भरता है उसमें संतोषजनक सेवा और उसके निर्वहन के तरीके को मूल विभाग में भी प्रदान की गई माना जाना चाहिए ताकि वह पदोन्नति का हकदार हो सके जो अक्सर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होती है। जो संकेत दिया गया है, वह बिल्कुल वही है जिसे आधिकारिक भाषा में 'अगला नियम' कहा जाता है, जिसके तहत प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी को कागजी-पदोन्नति दी जाती है और उसे मूल विभाग में एक उच्च पद पर दिखाया जाता है, यदि उसके नीचे के अधिकारी को पदोन्नत किया जा रहा हो। **ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम एमपी राज्य और अन्य**[7] में, प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को वापस भेजते समय, न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति मूल विभाग में उन सभी लाभों के हकदार होंगे जो कनिष्ठों को दिए गए थे और जो समान थे। स्थित है और

[6] AIR 1968 SC 868
[7] (1996) 7 SCC 260

आगे कहा गया है कि उनका राज्य प्रासंगिक तिथियों से ऐसे व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार करेगा जब उनसे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। **बिहार राज्य जल विकास निगम बनाम अरुण कुमार मिश्रा और अन्य**[8] में, निर्धारित किया गया था कि कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा एक विभाग से निगम में अपना ग्रहणाधिकार मूल विभाग में बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। **आर.एल. गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[9] में, यह देखा गया कि न्यायिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले सदस्य अपनी वरिष्ठता नहीं खो सकते, भले ही वह अपने जोखिम पर प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुना।

(8) बिना सहमति के याचिकाकर्ताओं को नवगठित जिले में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई अक्षम्य है। सभी व्यक्ति अपने मूल पदों पर वापस भेजे जाने के हकदार हैं। उनकी वरिष्ठता की गणना जिला गुड़गांव में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से की जाएगी और उस तारीख के बाद उस पद पर रहने वाले व्यक्तियों को जो भी पदोन्नति की पेशकश की गई थी, वह संबंधित याचिकाकर्ताओं को उस तारीख को दी जाएगी जब बाद में नियुक्ति की पेशकश की गई थी। पदोन्नति। इसका कोई मतलब नहीं होगा कि जो पद याचिकाकर्ताओं ने खाली किया है उसे बाद में नई नियुक्तियों से भरा गया है। यदि उन्हें अधिशेष माना जाना है, तो उन्हें या तो नवगठित जिले में पुन: समायोजित किया जा सकता है या उनकी सेवाएं कानून के अनुसार समाप्त कर दी जाएंगी। यदि डीआरडीए गुड़गांव में बाद

[8] AIR 1997 SC 2185
[9] AIR 1988 SC 968

में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की कार्यवाही के उदाहरण पर किसी भी अदालत के किसी भी आदेश के आधार पर ऐसे अधिशेष पदों की सेवा समाप्त करना असंभव हो जाता है, तब भी इसे याचिकाकर्ताओं को इनकार करने के आधार के रूप में नहीं लिया जाएगा। प्रत्यावर्तन का अधिकार. याचिकाकर्ताओं का प्रत्यावर्तन प्राप्त करने का अधिकार उस न्यायालय को दिखाया जाएगा जिसमें रिट याचिका लंबित है और यह उत्तरदाताओं के लिए न्यायालय के निर्देशों के अधीन उचित निर्णय लेने के लिए खुला होगा, जिसके वे कानून के अनुसार हकदार होंगे।

(9) रिट याचिकाएँ रुपये की लागत के साथ स्वीकार की जाती हैं। 10,000. प्रतिनियुक्ति के आदेश रद्द कर दिए गए हैं और याचिकाकर्ता अपने संबंधित पदों पर वापस आने के हकदार होंगे, जिस पर उन्होंने कब्जा किया था और उन्हें आगे पदोन्नति दी गई थी, जो उनके कनिष्ठों को दी गई थी। इसका कोई मतलब नहीं होगा कि प्रत्यावर्तन के समय किसी भी याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति के स्थान पर पदोन्नत किया गया है। वे उस पद पर बने रहेंगे जिसके वे हकदार थे और उन्हें पदोन्नत किया गया था यदि उनसे कनिष्ठ किसी अन्य कर्मचारी को पदोन्नत किया गया दिखाया गया था।

(10) रिट याचिकाएं उपरोक्त शर्तों पर स्वीकार की जाती हैं।

**अस्वीकरण :** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं

किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

**रितिज़ अरोड़ा**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)**

**(हरियाणा)**